नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 055
दि. 27.11.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

केंद्र ने महाराष्ट्र–गुजरात को दी बड़ी सौगात, पुणे मेट्रो फेज-2 और दो मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

(जीएनएस)। केंद्र सरकार ने बुधवार को महाराष्ट्र और गुजरात के लिए ऐसे फैसले लिए, जो आने वाले वर्षों में इन दोनों राज्यों की परिवहन व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र के चार जिलों को जोड़ने वाले दो महत्वपूर्ण मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को भी स्वीकृति मिली है। इन फैसलों को दोनों राज्यों के लिए वर्ष 2025 का बड़ा और ऐतिहासिक 'इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज' माना जा रहा है।

पुणे मेट्रो के दूसरे चरण के तहत लाइन 4 और 4A का निर्माण होगा, जिसकी कुल लंबाई 31.636 किलोमीटर होगी। योजना के मुताबिक खराड़ी से खड़कवासला तक फैली लाइन–4 और नल स्टॉप से मानिक बाग तक जुड़ने वाली लाइन–4A में कुल 28 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। लगभग 9,858 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना पांच वर्षों में पूरी करने का लक्ष्य रखती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये दोनों लाइनें पुणे के आईटी हब, औद्योगिक क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों और तेजी से बढ़ रहे आवासीय इलाकों को आपस में जोड़ेंगी। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना

के खर्च को साझा करेंगे। नई मेट्रो लाइनें पुणे की व्यापक गतिशीलता योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। खास बात यह है कि यह नेटवर्क स्वारगेट (लाइन 1), नल स्टॉप (लाइन 2) और अन्य मंजूर किए गए कॉरिडोर से आसानी से जुड़ जाएगा। हडपसर रेलवे स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध कराने से यात्रियों को रेल, मेट्रो और बस—तीनों के बीच सुगम मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके पूरा होने पर सोलापुर रोड, मगरपट्टा सिटी, सिंहगढ़ रोड, कर्वे रोड और पुणे–बेंगलुरु हाईवे जैसे भीड़भाड़ वाले मार्गों पर ट्रैफिक कम होगा। इससे न केवल यात्रा समय घटेगा बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी और शहर में सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने भारतीय रेलवे के दो अहम मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। लगभग 2,781 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली इन परियोजनाओं के तहत रेलवे नेटवर्क करीब 224 किलोमीटर तक बढ़ेगा। गुजरात के देवभूमि द्वारका क्षेत्र में ओखा से कनालुस तक 141 किलोमीटर लंबी दूसरी लाइन बिछाई जाएगी, जबकि महाराष्ट्र के बदलापुर–कर्जत सेक्शन में तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा। यह हिस्सा मुंबई उपनगरीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण कॉरिडोर है, जहां ट्रेनों का भार लगातार बढ़ रहा है। नई लाइनों के बन जाने से यात्रियों और मालगाड़ियों दोनों के लिए रेल यातायात सुचारू होगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव के अनुसार, इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 585 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, जिनकी कुल जनसंख्या करीब 32 लाख है। ये ट्रेन नेटवर्क ग्रामीण इलाकों को शहरों से और ज्यादा मजबूती से जोड़ेंगे, जिससे रोजगार, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी। सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में पश्चिम भारत—खासकर महाराष्ट्र और गुजरात—स्मार्ट, तेज और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में बड़े कदम उठाने वाला है।

रेल यात्रियों की शिकायत पर उठा बड़ा सवाल: हलाल मीट परोसने की नीति पर NHRC की सख्ती, रेलवे से दो हफ्ते में जवाब तलब

(जीएनएस)। नई दिल्ली की ठंडी सुबह में अचानक हलचल तब बढ़ गई, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारतीय रेल में परोसे जाने वाले भोजन को लेकर आई एक गंभीर शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया। शिकायत साधारण नहीं थी—आयोग के पास यह आरोप पहुंचा था कि रेलवे में यात्रियों को केवल हलाल प्रमाणित मांस ही परोसा जा रहा है। यह व्यवस्था, शिकायतकर्ता के अनुसार, न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है बल्कि उन हिंदू अनुसूचित जाति समुदायों की आजीविका पर भी गहरा प्रहार करती है जो परंपरागत रूप से मांस व्यवसाय पर निर्भर रहे हैं। शिकायत में कहा गया कि जब देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क केवल एक प्रकार के धार्मिक प्रचलन के अनुरूप खाद्य विकल्प रखता है, तो यह अनेक यात्रियों की आस्था और व्यक्तिगत चयन के अधिकारों को सीमित कर देता है। कई हिंदू और सिख यात्री ऐसी अनिवार्यता को अपनी धार्मिक परंपराओं के विपरीत बताते हैं। मामला केवल भोजन का नहीं, बल्कि संविधान में दिए गए उन अधिकारों का है जो

नागरिकों को समानता, गैर-भेदभाव, पेशे की स्वतंत्रता, सम्मानजनक जीवन और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं।

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने शिकायत प्राप्त होते ही इसे मानवाधिकारों के संभावित हनन के रूप में देखा। उनका कहना था कि भारतीय रेलवे एक सरकारी संस्था है और ऐसे में उसे देश की धर्मनिरपेक्ष भावना के अनुरूप हर यात्री की आस्था और उसकी व्यक्तिगत पसंद का सम्मान करना चाहिए। किसी एक पद्धति के मांस को अनिवार्य बनाना केवल भोजन का प्रश्न नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे लोगों की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ विषय है। एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आयोग का मानना है कि यह मामला संवेदनशील है और इसमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। यदि शिकायत के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह नीति न केवल अनेक समुदायों की आजीविका को प्रभावित कर सकती है, बल्कि यात्रियों को उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ विकल्प स्वीकार करने के लिए भी बाध्य कर सकती है।

देश के सबसे बड़े परिवहन नेटवर्क में लाखों लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। ऐसे में भोजन से जुड़ी किसी भी नीति का दायरा केवल ट्रेन की प्लेट तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह समाज के विविध समुदायों की भावनाओं और अधिकारों पर सीधा असर डालती है। अब सबकी निगाहें रेलवे बोर्ड की उस रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो अगले कुछ दिनों में सामने आएगी और यह तय करेगी कि यात्रियों की शिकायतें कितनी गंभीर और कितनी वैध हैं।

लालकिला धमाके की गुत्थी सुलझने की ओर, एनआईए ने उमर उन नबी को पनाह देने वाले सहयोगी सोयब को दबोचा

(जीएनएस)। दिल्ली की सरहद पर 10 नवंबर की वह भयावह शाम अभी भी लोगों के मन में कांपती है, जब लालकिला के पास खड़ी एक कार में हुए भीषण विस्फोट ने राजधानी को दहला दिया था। इस धमाके में दस से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई राहगीर गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस रात की दहशत में सिर्फ धमाके की आवाज़ ही नहीं थी, बल्कि उसके पीछे छिपी साजिश की लंबी परछाईं भी थी, जिसका खुलासा करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए लगातार अभियानों को तेज कर रही थी। इसी कड़ी में अब एक और अहम गिरफ्तारी हुई है, जिसने पूरे केस को एक नई दिशा दे दी है।

एनआईए ने फरीदाबाद निवासी सोयब नाम के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने मुख्य आरोपी आतंकी उमर उन नबी को न केवल अपने ठिकाने पर पनाह दी थी, बल्कि धमाके से पहले कई तरह की लॉजिस्टिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी। एजेंसी की मानें तो सोयब सिर्फ एक छिपाने वाला शख्स नहीं था, बल्कि वह पूरी साजिश की कड़ी का एक सक्रिय हिस्सा था—जो उमर को सुरक्षित आवाजाही, उससे संपर्क बनाए रखने, और उसे कुछ जरूरी सामग्री जुटाने में मदद कर रहा था। एनआईए की रडार पर वह कई दिनों से था, लेकिन उसकी गतिविधियों और संपर्कों की

गहन निगरानी के बाद ही उसे धर दबोचा गया। सोयब की गिरफ्तारी से यह मामला और खुलने लगा है। यह इस केस में सातवां नाम है जिसे अब तक एनआईए ने पकड़ा है। इससे पहले उमर उन नबी के छह सहयोगियों को देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया जा चुका है, और शुरुआती पूछताछ में यह साफ हुआ था कि यह साजिश अचानक नहीं बनी, बल्कि कई महीनों से इसकी जमीन तैयार की जा रही थी। उमर, जो इस पूरी साजिश का कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ने दिल्ली को निशाना बनाने के लिए कई स्थानों का निरीक्षण किया था। वह पिछले कुछ महीनों में नेपाल सीमा और जम्मू–कश्मीर के बीच कई बार आवाजाही करता रहा, ताकि खुद को जांच एजेंसियों की नजर से बचा सके।

एनआईए अधिकारियों के अनुसार, सोयब ने उमर को दिल्ली–एनसीआर में सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद की थी। उसने कुछ नकली दस्तावेजों की व्यवस्था भी करवाई थी, जिनकी मदद से उमर शहर के भीतर आसानी से घूम सके। यह भी सामने आया है कि धमाके से ठीक दो दिन पहले उमर कुछ समय के लिए सोयब के फरीदाबाद वाले घर में रुका था। जांच टीम को उस घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डिजिटल डेटा और मोबाइल फोन भी मिले हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि इनमें कई अहम सुराग छिपे हो सकते हैं।

दिल्ली धमाके की जांच अब कई राज्यों में फैली हुई है और एनआईए ने हर उस जगह पर छापेमारी तेज कर दी है, जहां से साजिश के सूत्र मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर की पुलिस भी इस मामले में एनआईए की टीमों के साथ मिलकर तलाशी अभियान चला रही है। एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस हमले के पीछे किसी बाहरी संगठन की फंडिंग या मार्गदर्शन जुड़ा हुआ है, या फिर यह समूह स्थानीय स्तर पर ही खुद को संगठित कर रहा था।

इस बीच दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने लालकिला और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, संवेदनशील बाजारों, पर्यटक स्थलों और मेट्रो नेटवर्क पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। शहरभर में हाई–अलर्ट जारी है और पुलिस की विशेष टीमें रात–दिन निगरानी में जुटी हैं।

सोयब की गिरफ्तारी से जांच आगे बढ़ने की उम्मीद मजबूत हुई है। एनआईए का कहना है कि यह मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है और जल्द ही पूरी साजिश की तस्वीर सामने आ सकती है। राजधानी में हुए इस दर्दनाक हमले की गूंज अभी भी लोगों के मन में है, और हर कोई इंतजार कर रहा है उस क्षण का जब इस कांड के हर दोषी को अदालत के कठघरे में खड़ा किया जा सकेगा। राजधानी की शांति को चुनौती देने वाले इस हमले की गुत्थी अब धीरे–धीरे सुलझ रही है—और सुरक्षा एजेंसियां दावा कर रही हैं कि वे इस बार किसी भी कड़ी को अधूरा नहीं छोड़ेंगी।

रेलवे टेंडर और लैंड फॉर जॉब घोटाले में राबड़ी देवी की याचिका पर CBI को नोटिस, अदालत ने मांगा जवाब

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में मंगलवार को एक अहम मोड़ आया जब रेलवे टेंडर घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मामलों में राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जवाब देने का निर्देश जारी किया गया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि सीबीआई अगली सुनवाई से पहले अपना पक्ष दर्ज कराए, ताकि अदालत यह तय कर सके कि याचिका को स्वीकार किया जाए या मौजूदा ट्रायल प्रक्रिया यथावत जारी रहे। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी, और इस तारीख तक सभी कानूनी तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

राबड़ी देवी ने अदालत में अर्जी दायर करते हुए मांग की कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई वर्तमान जज विशाल गोगने से हटाकर किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित की जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जज गोगने कथित रूप से पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं और सुनवाई को पूर्वनियत तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। राबड़ी देवी का कहना है कि अदालत की कार्यवाही के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि जज अभियोजन पक्ष की सहायता कर रहे हैं, जिससे निष्पक्ष सुनवाई की संभावना प्रभावित होती है। यही आधार है कि वह अपने और परिवार के खिलाफ लंबित चारों मामलों के स्वतंत्र ट्रायल की मांग कर रही हैं।

मामले की पृष्ठभूमि यह है कि 13 अक्टूबर को जज गोगने ने रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किए थे। सभी आरोपितों ने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल का सामना करने की इच्छा जताई।

सीबीआई ने पहले ही अदालत को सूचित कर दिया था कि उनके पास आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। ईडी और सीबीआई दोनों ने मिलकर कुल 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के साथ कई कंपनियां और कारोबारी भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में अदालत ने लालू यादव और उनके परिवार को नियमित जमानत प्रदान की थी। अब सबकी निगाहें सीबीआई के जवाब और अदालत के निर्णय पर टिकी हैं। यदि अदालत राबड़ी देवी की याचिका को स्वीकार करती है, तो मामलों की सुनवाई किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित हो सकती है, जिससे ट्रायल की दिशा बदल सकती है। वहीं, अगर याचिका खारिज होती है, तो वर्तमान ट्रायल प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी। इस फैसले से न केवल लालू परिवार की कानूनी रणनीति प्रभावित होगी, बल्कि यह भी स्पष्ट होगा कि विशेष अदालत और जांच एजेंसियों के बीच संतुलन और निष्पक्षता कितनी प्रभावी रूप से बनाए रखा जा रहा है। राजनीतिक और कानूनी गलियारों में इस मामले ने हलचल मचा दी है। यह मामला केवल व्यक्तिगत आरोपितों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय न्याय प्रणाली में निष्पक्षता, जांच एजेंसियों की भूमिका और अदालत के तटस्थ निर्णय की संभावना पर भी प्रश्न खड़ा करता है। पूरे देश की नजरें अब अदालत के अगले आदेश पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि यह विवादास्पद ट्रायल किस दिशा में आगे बढ़ेगा और देश की जनता के कानूनी विश्वास को कितना प्रभावित करेगा।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030: अहमदाबाद बनेगा खेलों और संस्कृति का ग्लोबल महाकेंद्र, दुनिया की निगाहें गुजरात पर

(जीएनएस)। अहमदाबाद की धड़कन अब सिर्फ़ साबरमती के किनारे तक सीमित नहीं रहेगी। शहर ने पहले ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम से अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई थी, लेकिन अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के ज़रिए यह शहर वैश्विक खेलों और भारतीय संस्कृति का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। विश्व के खेल प्रेमियों की निगाहें भारत पर टिकी हैं, और अहमदाबाद उन्हें सिर्फ़ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खेलों, उत्सव और तकनीक का एक अद्वितीय अनुभव देने वाला शहर बनने जा रहा है।

सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव—एक खेलों का साम्राज्य

रिवरफ्रंट पर 215 एकड़ में तैयार हो रहे इस सुपर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 4600 करोड़ रुपए है। यह केवल स्टेडियम या एरेना का परिसर नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा मेगा-ज़ोन बनेगा जहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम, एरेना, एक्वेटिक्स सेंटर के साथ-साथ सांस्कृतिक आयोजन जैसे गरबा नाइट्स, ओपन कल्चरल फेस्टिवल और योग महोत्सव भी आयोजित होंगे। यानी अहमदाबाद में खेल और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा, और यह शहर सिर्फ़ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों के नक्शे पर नए मुकाम पर खड़ा होगा।

एक शहर, एक पूरा स्पोर्ट्स यूनिवर्स

अहमदाबाद का यह प्रोजेक्ट यूरोप और अमेरिका के किसी भी खेल केंद्र को टक्कर दे सकता है। इंडोर स्टेडियम, फुटबॉल एरेना, शूटिंग सेंटर, हॉकिंग एरेना—all in one—यानी एक ही सुपर-ज़ोन में सभी खेल सुविधाएं। इसके साथ ही मेट्रो नेटवर्क, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर को पूरी तरह से विश्वस्तरीय कॉन्वीनियंस देंगे, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों की पहुंच और सुविधा आसान होगी। यह शहर अब खेल प्रेमियों के लिए सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनने जा रहा है।

खिलाड़ियों का ड्रीम होम—कॉमनवेल्थ विलेज

सुगढ़-भाट (136 एकड़) और कराई (143 एकड़) में बनने वाले दो मेगा एथलीट विलेज खिलाड़ियों के लिए लग्ज़री और हाई-टेक का परफेक्ट संगम होंगे। 3000 से अधिक अल्ट्रा-मॉडर्न अपार्टमेंट, स्पोर्ट्स साइंस लैब, रिकवरी सेंटर, जिम, पूल और 24x7 वेलनेस सुविधाओं से लैस यह विलेज खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और आराम दोनों के लिए प्रेरणा देगा। यह न केवल भारतीय एथलीटों के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए भी आकर्षण का केन्द्र बनेगा, जो अहमदाबाद को खेलों की दुनिया में सबसे चर्चित स्थान बनाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 सिर्फ़ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान को नई ऊँचाई देने वाला प्रोजेक्ट है। अहमदाबाद अब दुनिया को दिखाएगा कि कैसे खेल, संस्कृति, तकनीक और आधुनिक सुविधाओं को जोड़कर कोई शहर खुद को ग्लोबल स्पोर्ट्स और कल्चरल हब के रूप में स्थापित कर सकता है। यही वजह है कि 2030 में पूरी दुनिया की निगाहें गुजरात की इस धड़कती नगरी पर होंगी, और यह शहर खेलों और उत्सव का नया बादशाह बनकर उभर कर सामने आएगा।

संपादकीय

शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि एक सुधार

भले ही श्रीलंकाई संकट के समाधान हेतु भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा जाना तत्कालीन सरकार का फैसला रहा हो, लेकिन वास्तव में भारतीय सैनिक राष्ट्र के हितों और सैन्य दायित्वों के लिये ही लड़े थे। इस फैसले का उद्देश्य श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा और उनके न्यायसंगत पुनर्वास के लिये पहल करना भी रहा है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि भारतीय शांति सेना यानी आईपीकेएफ के पूर्व सैनिकों में इस बात को लेकर लंबे समय से रोष व्याप्त रहा है कि आईपीकेएफ सैनिकों के बलिदान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। अब सरकार व सेना ने इस कमी को पूरा करने की दिशा में कम से कम एक पहल तो की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करना, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बाबत श्रद्धांजलि संदेश प्रेषित किया है। भले ही शीर्ष अधिकारियों द्वारा की गई यह पहल एक प्रतीकात्मक सुधार हो, लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया सार्थक कदम है। हालांकि देर से ही सही, ये प्रयास श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए 1,171 भारतीय सैनिकों को उचित सम्मान देने में रही एक कमी को दूर करने का प्रयास कहा जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में करीब तीन हजार से ज्यादा सैनिक घायल भी हुए थे। इससे पूर्व कई वीर सैनिकों को वीरता पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। लेकिन एक टीस के साथ कहा जाता रहा है कि यह अकसर भुला दिया जाने वाला युद्ध रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोलंबो में भारतीय शांति रक्षक सेना और पलाली में 10-पैरा के शहीदों के लिये स्मारक का निर्माण किया गया था। यह विडंबना ही है कि आईपीकेएफ के पूर्व सैनिक, शहीदों की विधवाएं और उनके परिजन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर निजी स्तर पर स्मरणोत्सव आयोजित करते रहे हैं। निश्चित ही देश के हितों के लिये चलाये गए किसी भी सैन्य अभियान में शहीद हुए सैनिकों को सामान्य युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तरह पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए।

दरअसल, ऑपरेशन पवन में शहीद हुए सैनिकों के परिजन और युद्ध में भाग लेने वाले जवान भी उन्हें पर्याप्त सम्मान दिए जाने की आस लंबे समय से रखते रहे हैं। वर्षों से उनकी मांग रही है कि साल 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध के शहीदों की याद में मनाये जाने वाले खास दिनों की तरह 'ऑपरेशन पवन' की याद में भी एक विशेष दिन की घोषणा की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शहीद सैनिकों के परिजनों की एक टीस उन्हें दशकों से सालती रही है। चूंकि ऑपरेशन पवन में शहीद हुए कई सैनिकों का अंतिम संस्कार या दफनाने की प्रक्रिया विदेशी धरती पर पूरी हुई थी, इसलिए उनके परिजन शहीद सैनिकों के अवशेषों को वापस भारत लाने की नीति को सुव्यवस्थित करने की मांग करते रहे हैं। वे एक ऐसे आयोग के गठन की भी मांग करते रहे हैं जो शहीद सैनिकों के पार्थिव अवशेष को वापस भारत लाने की नीति को तार्किक बना सके। उनकी मांग रही है कि उन अवशेषों को भारत लाकर आईपीकेएफ का एक स्मारक बनाकर, उसमें सम्मान के साथ स्थानांतरित किया जाना चाहिए। निस्संदेह, किसी भी देश के वीर शहीदों के स्मारक सामूहिक स्मृति के प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सशस्त्र बलों द्वारा दिए गए बलिदान के लिये एक सम्मान और स्मरण स्थल के रूप में चिरस्थायी श्रद्धांजलि के रूप में होते हैं। निर्विवाद रूप से इस बहुप्रतीक्षित मांग को हकीकत में बदलने के लिये चाहे कितनी भी जटिलताएं क्यों न हो, सैनिकों के पराक्रम और बलिदान को कम करके आंकने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। यदि हम वीर सैनिकों के बलिदान को समुचित सम्मान देते हैं तो इससे तमाम सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। इस दिशा में अविलंब सार्थक पहल किया जाना वक्त की जरूरत ही है।

आचरण का हिस्सा बने संविधान की भावना

> जब हम समता की बात करें तो वह एक भारतीय समाज का उदाहरण हो; जब हम स्वतंत्रता की बात करें तो उसमें स्वतंत्रता के सारे प्रतिमान दृष्टिगोचर होते हों, जब हम न्याय की बात करें तो वह हर क्षेत्र में हर भारतीय को मिलने वाला न्याय हो। तब, और सिर्फ तब, हम सही अर्थों में संविधान दिवस मनाने के अधिकारी होंगे।

पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी ऐसी दो तिथियां हैं जब तिरंगा लहरा कर अपना देश-प्रेम प्रकट करना हमें ज़रूरी लगता है। इसमें पहली तिथि (15 अगस्त, 1947) तो वह है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और दूसरी (26 जनवरी, 1950) हमें अपने लिए एक संविधान बनाने की याद दिलाती है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके अनुसार हमने अपना जीवन संचालित करने का संकल्प किया था। इसी संदर्भ में एक तिथि और भी है जो हमें अपने संविधान के प्रति निष्ठा की याद दिलाती है—वह तिथि है 26 नवम्बर। वर्ष 1949 में इसी दिन हमारी संविधान सभा ने भारत के संविधान को आत्मार्पित किया था, जो दो माह बाद देश पर लागू हुआ।

हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी माने जाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर की 126वीं जयंती पर, दस साल पहले, भारत सरकार ने 26 नवम्बर को संविधान-दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। तब से हर साल इस दिन कृतज्ञ राष्ट्र अपने संविधान-निर्माताओं को याद करता है, और यह संकल्प दुहराता है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आधार पर एक नया समाज बनायेंगे। यह भी शपथ ली जाती है कि हम सांविधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। पर क्या हम यह काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं?

हमारा संविधान हमें सिखाता है कि भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग का क्यों न हो, समान है। समता के इस सिद्धांत का मतलब है भारतीय गणतंत्र का हर नागरिक संविधान की दृष्टि में किसी अन्य से किसी भी तरह कमतर नहीं है। सबके अधिकार बराबर हैं— और सबके कर्तव्य भी। इस समता के अभाव में न स्वतंत्रता का कुछ अर्थ रह जाता है और न ही न्याय और बंधुता का। अब हमें अपने आप से यह पूछना

है कि समता के इस मानदण्ड पर हम कितने खरे उतरते हैं। जिस जनतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपने लिए स्वीकारा है उसमें मतदान का बहुत व्यापक अर्थ है, और बहुत बड़ा अर्थ है। मतदान के द्वारा हम न केवल उनका चुनाव करते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व अथवा नेतृत्व करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि हम न्याय और बंधुता के पक्ष में खड़े हैं; हम सिर्फ अपने ही हित के लिए नहीं, अपने ही जैसे दूसरे नागरिकों के कल्याण के बारे में भी सोचते हैं। मतदान वस्तुतः व्यक्तियों का नहीं, एक व्यवस्था का चुनाव है। यह बात समझने और स्वीकारने के बाद हमें यह सोचना है कि मतदान केंद्र पर जाकर हम जो वोट डाल आये हैं, क्या वह उन आदर्शों और मूल्यों के पक्ष में हुआ है या फिर अपने स्वार्थों और अपनी अज्ञानता के चलते हम कोई घटिया समझौता कर आये हैं? ऐसा कोई भी समझौता किसी अपराध से कम नहीं होता। इसलिए, पेटी में वोट डालने अथवा मशीन का बटन दबाने से पहले जागरूक मतदाता को दस बार सोचना चाहिए कि उसका यह कार्य उस संविधान के अनुरूप है या नहीं जिसने हमें मतदान का अधिकार दिया है?

बहुत अच्छा है हमारा संविधान। एक पूरा जीवन-दर्शन झलकता है इसमें। हमारे संविधान-निर्माताओं ने हर बात को बड़ी गहराई और विस्तार से सोचा है। पर डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवम्बर, 1949 को, यानी संविधान स्वीकार किये जाने से एक दिन पहले संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में एक चेतावनी दी थी। उन्होंने चेताया था, 'संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वह विफल हो जायेगा।' बड़ी शिद्दत से याद किया जाता है संविधान सभा में दिये गये उनके इस भाषण को। उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि समानता और बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तीसरी चेतावनी जो उन्होंने देशवासियों को दी थी, वह यह थी कि राजनीति में व्यक्ति-पूजा तानाशाही की ओर ले जाती है। सवाल उठता है क्या हमारे संविधान के शिल्पी की इन बातों के बारे में हम कभी सोचते हैं? दुर्भाग्य से इस प्रश्न का उत्तर 'हां' में नहीं है। हम और हमारे नेता संविधान के प्रति आदर दिखाने में भले ही पीछे न रहते हों, पर संविधान को सिर झुकाना और बात है, संविधान के प्रति ईमानदारी से निष्ठावान होना और बात। हमने अपने बड़े-बड़े नेताओं को, सबसे बड़े नेता को भी, न जाने कितनी बार संविधान की कस्में खाते देखा है, हमारे नेता यह कहने में भी संकोच नहीं करते कि देश का संविधान उनके लिए सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक है। पर इस सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक के प्रति उनका व्यवहार कैसा है? संविधान समानता की बात करता है, हमारे नेता असमानता की होड़ में लगे दिखाई देते हैं; संविधान कहता है धर्म या जाति के आधार पर देश में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए, हमारे नेता धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाने में लगे रहते हैं। मेरा धर्म और तेरा धर्म की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लोगों को इस बात पर भी आपत्ति है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 'रघुपति राघव राजाराम' वाले भजन में 'ईश्वर-अल्लाह तेरो नाम' क्यों जोड़ दिया था! हमारा संविधान देश के नागरिकों के बीच बंधुता के आदर्श की दुहाई देता है, हम इस आदर्श की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं! डॉक्टर अम्बेडकर ने प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था और परम्पराओं का हवाला देते हुए चेताया था, लोकतंत्र का यह सुनहरा इतिहास अब बीते कल की बात होकर रह गया है। अब हमें नये सिर से एक नये लोकतंत्र को सजाना है, उसे मज़बूत बनाना है। उन्होंने कहा था अपना यह प्राचीन लोकतंत्र हम एक बार खो चुके हैं, डर है, फिर न खो बैठें। सवाल उठता है वह डर हमें क्यों नहीं लगता? लगना चाहिए यह डर। और फिर इस डर से मुकाबला करने की एक उमंग भी जगनी चाहिए हमारे भीतर। जब हम अपने जनतांत्रिक संविधान की दुहाई देते हैं तो हमें डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 'इस नये पैदा हुए जनतंत्र के लिए इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जनतंत्र का ढांचा तो बना रहे पर वास्तविकता यह हो कि तानाशाही उसकी जगह ले ले।'

इन सारे खतरों के बारे में लगातार सोचते रहने की आवश्यकता है। काल्पनिक नहीं हैं ये खतरे। हम मान कर चल रहे हैं कि हमारे जनतंत्र को कोई खतरा नहीं है, बहुत मज़बूत है हमारी बुनियाद। पर यह मज़बूती खोखली भी सिद्ध हो सकती है। मज़बूत जनतंत्र का मतलब है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आदर्शों में विश्वास करने वाला जनतंत्र। सच तो यह है कि तभी यह सही मानों में जनतंत्र कहला सकता है जब हमारे संविधान के ये चार स्तम्भ हमारी सोच और विश्वास का, हमारे व्यवहार का हिस्सा बनें। जब हम समता की बात करें तो वह एक भारतीय समाज की उदाहरण हो; जब हम स्वतंत्रता की बात करें तो उसमें स्वतंत्रता के सारे प्रतिमान दृष्टिगोचर होते हों, जब हम न्याय की बात करें तो वह हर क्षेत्र में हर भारतीय को मिलने वाला न्याय हो। तब, और सिर्फ तब, हम सही अर्थों में संविधान दिवस मनाने के अधिकारी होंगे।

लेकिन समाज को बांटने वाली जो स्थितियां आज देश में दिख रही हैं, कोई धर्म की दुहाई दे रहा है, कोई जाति के नाम पर समर्थन मांग रहा है, उससे एक भय-सा लगने लगा है। विश्व कवि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने एक भय-मुक्त वातावरण में अपने देश के उदय होने की प्रार्थना की थी, वह प्रार्थना तभी पूरी हो सकती है, जब हम समाज को बांटने वाली ताकतों को सफल न होने दें। नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का तकाज़ा है कि हम अपने संविधान की भावना को अपने आचरण का हिस्सा बनायें। इस संदर्भ में अभी जो दिख रहा है, वह कुल मिलाकर निराश ही करने वाला है। ज़रूरी है कि हम इस अवधारणा को अपनी सोच और व्यवहार का हिस्सा बनायें कि सबसे पहले, और सबसे बाद में भी, हम भारतीय हैं, फिर कुछ और। आमीन।

प्रेरणा

हर साल की छुट्टियों का मौसम

हर साल जब दिसंबर की ठंड अपनी दस्तक देने लगती है और हवा में अदृश्य-सा धुआँ तैरता है, तभी अख़बारों के पन्नों पर और मोबाइल स्क्रीन के रंगीन चकौरों में एक बड़ा बदलाव शुरू हो जाता है। अगले साल का कैलेंडर अभी टँगा भी नहीं होता, लेकिन अगले साल की छुट्टियों के सपने बनने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा देश एक साथ अपनी जेब में घुसा हुआ फोन निकालकर देख रहा हो कि अगले साल कितने दिन काम करना है और कितने दिन सांसें भरकर जिया जा सकता है। जिन लोगों के घरों में पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हों, वहाँ यह छुट्टियों की लिस्ट किसी देव-पुराण की तरह पूजनीय हो जाती है। मानों हर छुट्टी कोई वरदान हो और हर त्योहार एक गुप्त दरवाज़ा जो जीवन को अस्थायी ही सही, पर बेहद मीठी आज़ादी दे देता हो। सरकारी नौकरी की अपनी एक चमक है—एक अलग ही किस्म का गौरव, जैसे किसी ने समाज के दुपट्टे पर एक चमकदार सितारा टाँक दिया हो। जिन परिवारों में एक भी सरकारी नौकरी वाला न हो, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर हल्का-सा धूल का परत-सा बैठ जाता है। लोग कहते भले न हों, पर मानते जरूर हैं कि सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि पहचान और सुरक्षा का प्रमाण-पत्र है। यही कारण है कि जिन घरों में एक व्यक्ति सरकारी सेवा में होता है, वह दूसरे को भी उसी राह पर भेजता है। कोचिंग सेंटरों की भीड़ इसे प्रमाणित करती है—देश निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, पर मन अभी भी पक्की नौकरी की छाँव ढूँढता है। अगले साल की छुट्टियों की सूची जब अख़बार में छपती है, तो बहुत-से लोग चाय की चुस्की रोककर पहले छुट्टियों पर नजर डालते हैं, फिर बाकी खबरों पर। यह सूची कई लोगों के लिए बस छुट्टियां नहीं, बल्कि नए साल की उम्मीदों, यात्राओं, आराम और परिवार के साथ बिताए पलों का खाका होती है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि दिवाली और बड़े त्योहार रविवार को पड़ रहे हैं, उत्साह किसी फटे गुब्बारे की तरह ढीला पड़ जाता है। यह रविवार वाला खेल बड़ा बेरहम है—जिस रविवार को छुट्टी होती ही है, उसी दिन बड़े त्योहार डाल देती है किस्मत। लोग मन ही मन सोचते हैं कि काश त्योहार सोमवार को पड़ते तो पूरा सप्ताह रोशन हो जाता।

धार्मिक-वैज्ञानिकों की दयालुता कभी-कभी त्योहार को दो दिनों का बना देती है, लेकिन यह सब किस्मत पर निर्भर करता है। कई बार वैकल्पिक अवकाश भी रविवार को गिरते हैं, जिससे कर्मचारी ऐसे निराश होते हैं जैसे किसी बच्चे को नई खिलौना कार दिखाकर छीन ली जाए। पर जब कोई छुट्टी शुक्रवार या शनिवार को पड़ती है, तब जीवन में एक अजीब-सी मिठास घुल जाती है। उस छुट्टी में एक दिन और जोड़ दो—और बन जाता है छोटा सा पर्व, एक चुपचाप खिलता हुआ पहाड़ी फूल जैसा सप्ताहांत।

कुछ छुट्टियाँ जब शनिवार या सोमवार को आती हैं तो दफ्तर जाने वाले लोगों के चेहरों पर अलग ही चमक आ जाती है। लेकिन अगर वही छुट्टी दूसरे शनिवार को पड़ जाए, तो उसका असर ऐसा होता है जैसे किसी ने पहले से खाली पड़े घड़े में एक और छेद मार दिया हो। छुट्टी तो थी, लेकिन मिली ही कहाँ?

अगले साल राष्ट्रीय अवकाश वही तीन हैं, पर धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों की संख्या पूरे उन्नीस। और देश के कुछ राज्यों में तो छुट्टियों का खजाना इतना भरा हुआ है कि पूरा तीस-तीस दिन अवकाश के होते हैं। ऐसे राज्यों के कैलेंडर देखकर बाकी राज्यों के लोग ईर्ष्या में डूब जाते हैं—मानो कोई पड़ोसी अचानक नया बंगला बना ले और बाकी लोग अपनी परछाई को ही ढाढ़स देते रह जाएँ।

सामाजिक समझदारों का एक तबका है जो मानता है कि चाहे त्योहार रविवार को ही क्यों न आए, उसकी छुट्टी किसी और ऐसे दिन दे देनी चाहिए जब पहले से अवकाश न हो। आखिर सरकारी कर्मचारी भी इंसान हैं, उनकी खुशियों की कीमत भी होनी चाहिए। सरकार जब अपने फैसले मनमाने ढंग से ले लेती है—सड़कें खोदने से लेकर टैक्स बदलने तक—तो छुट्टियों में थोड़ी-सी उदारता क्यों नहीं दिखा सकती?

और राजनीति के मंच पर तो छुट्टियाँ भी वोटों का साधन बन सकती हैं। अगर सत्ताधारी सोच लें कि छुट्टियों को पुनर्नियोजित करके कर्मचारियों की खुशियों में इजाफ़ा कर दिया जाए, तो चुनाव से पहले उनकी झोली में वोटों का कोहरा ही कोहरा जमा हो जाएगा। आखिर जनता को खुशी देने का यह इतना सरल तरीका है कि उससे आसान शायद ही कुछ हो।

यही है हर साल की छुट्टियों का किस्सा—जहाँ इच्छा, राजनीति, गणना, परिवार और छोटे-छोटे सपने एक साथ घूमते रहते हैं। यही वह कहानी है जहाँ जिंदगी अपनी रफ्तार भूलकर कुछ देर के लिए रुक जाती है, और कैलेंडर के पन्ने इंसान के दिल में नई उम्मीदों के दीपक जला देते हैं।

भारत-कनाडा के रिश्तों में नई गर्माहट बड़े बदलाव का संकेत

भारत और कनाडा के रिश्तों पर पड़ी बर्फ धीरे-धीरे पिघल रही है और दोनों देशों के बीच एक नए विश्वास, सहयोग और साझेदारी का वातावरण आकार ले रहा है। वैश्विक राजनीति के बदलते स्वरूप, व्यापारिक हितों और तकनीकी साझेदारियों की बढ़ती जरूरतों ने दोनों देशों को पुनः संवाद और सहयोग की राह पर लौटने के लिए प्रेरित किया है। जून से शुरू हुआ यह सकारात्मक बदलाव अब व्यापक रूप में दिखाई देने लगा है, जिसका संकेत हाल ही में की गई द्विपक्षीय बैठकों, उच्चस्तरीय संपर्कों और आर्थिक सहयोग की घोषणाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य एवं कनाड़ा द्वारा अब नागरिकता के बंद दरवाजे खोलने की घोषणा इस परिवर्तन की गहराई और व्यापकता को रेखांकित करती है। यह लक्ष्य केवल व्यापार बढ़ाने का संकल्प मात्र नहीं है बल्कि यह उस नये दौर की प्रतीकात्मक दस्तक है जिसकी ओर दोनों देश बढ़ रहे हैं और इससे दोनों देशों को फायदा होगा। पिछले कुछ समय में भारत और कनाडा के रिश्तों में जिस तरह तनाव और अविश्वास ने जगह बनाई थी, वह दोनों देशों के लंबे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन-आधारित संबंधों के विपरीत था। खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा में बढ़ती गतिविधियों, राजनीतिक आरोपों-प्रत्यारोपों और न्यायिक प्रक्रियाओं ने दोनों देशों के रिश्तों में गहरी खटास पैदा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच दूरी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी और कूटनीतिक संवाद लगभग ठहर-सा गया था। जस्टिन ट्रूडो ने राजनीतिक दबाव एवं स्वार्थ के चलते भारत से ऐतिहासिक संबंधों को धुंधलाया, जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता भी है। लेकिन अब नई सरकार के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नये जोश, आत्मीयता एवं संवेदनाओं के साथ भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों, व्यापारिक अवसरों के विस्तार और नई आर्थिक-रणनीतिक जरूरतों ने दोनों पक्षों को यह अहसास कराया कि रिश्तों का ठहराव किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। इसी समझ ने दोनों देशों को संवाद के नये पुल बनाने और पुराने अवरोधों को पीछे छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ाया।

नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी की जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। यह मुलाकात भले ही मुख्य सत्रों के इतर हुई, लेकिन उसका संदेश अत्यंत गहरा और दूरगामी था। यहां दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी इनोवेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और कनाड़ा के पास डिफेंस, स्पेस, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी और एजुकेशन समस्त कई क्षेत्रों में सहयोग एवं सहमति बढ़ाने के मौके हैं। यह सहमति केवल औपचारिकता नहीं बल्कि रिश्तों को एक नए मोड़ पर लाने का संकेत थी। कनाडा एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी शक्ति है और भारत विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी प्रतिभा का केंद्र बन चुका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं जिनकी दिशा अब खोली जा रही है। वैसे भी भारत के स्टूडेंट्स के लिये अब भी कनाड़ा सबसे पसंदीदा जगहों में एक हैं। कनाडा अपने नागरिकता कानून में भी बदलाव करने जा रहा है, उससे भी भारतीयों को फायदा होने की व्यापक संभावनाएं है।

पीयूष गोयल के वक्तव्य में दिखती आर्थिक साझेदारी की दृष्टि इस बात का परिचायक है कि भारत और कनाडा अब केवल राजनीतिक संवाद से आगे बढ़कर व्यावहारिक सहयोग के नए आधार बना रहे हैं। 50 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य बेहद महत्वाकांक्षी है, लेकिन यह उन आर्थिक संभावनाओं का वास्तविक अनुमान भी है जो दोनों देशों की नीतियों, संसाधनों और क्षमताओं में मौजूद है। भारत कनाडा के लिए एक विशाल बाजार है और कनाडा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा, खनिज, कृषि और तकनीकी साझेदार। इसी परस्पर निर्भरता और जरूरत ने दोनों देशों को फिर से एक-दूसरे की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। अब जरूरी है कि विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी रखते हुए जल्द समझौते तक पहुंचा जाये।

हाल के वर्षों में दुनिया बहुधूरवीय स्वरूप की ओर बढ़ रही है। अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस और पश्चिम एशिया जैसे शक्ति केंद्रों के बीच उभर रही नई अनिश्चितताओं ने मध्यम और उभरती शक्तियों को नए साझेदार तलाशने के लिए विवश किया है। भारत और कनाडा इस वैश्विक संरचना में ऐसे दो देश हैं जिनके पास जनसांख्यिकीय शक्ति, आर्थिक संसाधन, शिक्षा-तकनीक की क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों का साझा आधार मौजूद है। ऐसे में इन दोनों का साथ आना न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए आवश्यक है बल्कि एक नई वैश्विक संरचना के निर्माण में भी उपयोगी हो सकता है। यह संरचना सहयोग, नवाचार, जलवायु न्याय, हरित तकनीकों और स्थायी विकास पर आधारित हो सकती है। कनाडा में भारतीय मूल की बड़ी आबादी दोनों देशों के रिश्तों को मानवीय और सामाजिक आधार भी देती है। जब भी रिश्तों में तनाव आया, प्रवासी भारतीय समुदाय उसके बीच पुल की तरह खड़ा दिखाई दिया है। यही समुदाय आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक रिश्तों को नई दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह समुदाय न केवल कनाडा के आर्थिक विकास का हिस्सा है बल्कि भारत-कनाडा संबंधों की गहरी कड़ी भी है। यही कारण है कि दोनों सरकारों ने इस सामाजिक संबंध को और मजबूत करने का प्रयास शुरू किया है जिससे गलतफहमियाँ कम हों, लोगों के बीच भरोसा बढ़े और राजनीतिक विवादों का असर द्विपक्षीय रिश्तों पर सीमित रहे।

वर्तमान दौर में भारत की वैश्विक छवि एक निर्णायक, प्रभावशाली और विश्व-हितैषी शक्ति के रूप में उभर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक शैली, वैश्विक मंचों पर सक्रियता और विकास-शांति आधारित विदेश नीति ने भारत की स्थिति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दूसरी ओर कनाडा भी एक स्थिर लोकतंत्र और बहुसांस्कृतिक देश के रूप में वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है।

अभियान

वैकुण्ठ के द्वार से पृथ्वी तक फैलती वह दिव्य कथा, जिसमें दो प्रहरी दानव बने भगवान अवतरित हुए और ब्रह्मांड ने भक्ति का सबसे विलक्षण रूप देखा

वैकुण्ठ की उस अविनाशी सुबह में, जहाँ प्रकाश भी भगवान के चरणों में ठहरकर अपनी चमक समर्पित कर देता है, दो दिव्य योद्धा प्रहरी बनकर खड़े थे—जय और विजय। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, निगाहों में साहस था और हृदय में भगवान विष्णु के प्रति ऐसा समर्पण जैसे हर धड़कन केवल उनका नाम जपे। ये दोनों द्वारपाल केवल रक्षक नहीं थे, बल्कि वैकुण्ठ की स्थिरता और शांति के प्रतीक थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी वही जय और विजय दानव रूप लेकर पृथ्वी पर जन्म लेंगे और भगवान स्वयं उनके वध के लिए अवतरित होंगे। पर यही तो भगवान की लीला है—अकल्पनीय, अप्रत्याशित और अनंत रहस्यों से भरी। एक दिन सनकादिक कुमार—सनक, सनंदन, सनातन और सनत्कुमार—अपने तप और ज्ञान से दीप्तिमान, भगवान के दर्शन हेतु वैकुण्ठ पहुँचे। वे बालक के रूप में थे, परन्तु उनकी आत्मा कालातीत थी। जब वे द्वार पर

पहुँचे तो जय और विजय ने अपने कर्तव्यवश उन्हें रोक दिया। एक क्षण के इस रोकने में कठोरता का कोई भाव नहीं था, परंतु ऋषियों ने इसे अपमान समझा। उन्होंने क्रोध में कहा कि तुम दोनों अगले तीन जन्मों में दानव बनकर जन्म लोगे, और भगवान के सान्निध्य से दूर रहोगे।

यह वाणी उनके सिर पर बिजली बनकर गिरी।

जय और विजय के हृदय में हलचल मच गई। वे काँपते हुए भगवान विष्णु के चरणों में पहुँचे, और दीन भाव से बोले—"प्रभु, हम से भूल हो गई है। हमें आपसे दूर होने का दंड मत दीजिए।" भगवान ने उन्हें स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ उठाया और कहा—"यह भी मेरी ही लीला है। तुम्हें तीन बार दानव बनकर जन्म लेना होगा, पर हर जन्म में मैं स्वयं तुम्हारा वध करने आऊँगा, और अंत में तुम मेरे पास लौट आओगे। तुम भक्त हो, इसलिए दानव भी बनोगे तो मेरे ही लिए बनोगे।"

यही से आरंभ हुआ तीन जन्मों का वह अद्भुत अध्याय, जिसे सुनकर आज भी मन रोमांच से भर जाता है।

पहला जन्म—हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु।

हिरण्याक्ष अपार बल का स्वामी था। उसका अहंकार पृथ्वी को लेकर पाताल तक चली गया। समुद्रों में हाहाकार मच गया, देवताओं ने प्रार्थना की और भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। वह विराट वराह—जिसके दाँतों पर पृथ्वी का भार था और गर्जना से दिशाएँ काँप रही थीं—हिरण्याक्ष के सामने अविचल खड़ा था। युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं था; वह धर्म और अधर्म, स्थिरता और अहंकार का टकराव था। अंत में हिरण्याक्ष मारा गया और जय के पहले दानवी जन्म का अंत हुआ।

परंतु उसी समय उसका भाई हिरण्यकशिपु, जो ब्रह्मा से वरदान पाकर मृत्यु से लगभग परे हो गया था, देवलोक तक को अपने पैरों तले रौंदना चाहता था। उसका क्रोध ब्रह्मांड की सीमाएँ तोड़ रहा था। पर उसके ही घर में एक छोटा बालक बैठा था—प्रह्लाद—भगवान विष्णु का परम भक्त। हिरण्यकशिपु ने जब प्रह्लाद को भी अपने अहंकार के सामने झुकाना चाहा, तब भगवान को हस्तक्षेप करना ही था।

स्तंभ पर हथौड़े की आवाज पड़ी और वह फट गया। उसमें से प्रकट हुआ वह दिव्य रूप—नरसिंह। सिंह का मुख, मनुष्य का शरीर, परंतु संपूर्ण शक्ति का केंद्र। यह रूप इतना उग्र था कि देवता भी निकट आने में संकोच कर रहे थे। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को गोद पर लिटाकर नखों से चीर दिया, और उसी प्रहार के साथ विजय के दानवी जन्म का अंत हुआ।

इस कथा का वास्तविक अर्थ यह है कि भगवान की योजना साधारण नहीं होती। भक्तों के लिए रास्ते कभी सरल नहीं होते। जय और विजय को दानव बनना पड़ा, युद्ध करना पड़ा और भगवान के हाथों मारे जाना पड़ा—पर हर जन्म उन्हें भगवान के और निकट ले जाता गया। बाद में वे रावण और कुंभकरण बने, फिर शिशुपाल और दन्तवक्र। हर जन्म में भगवान ने अवतार लिया—राम बनकर, कृष्ण बनकर—और हर बार अपने इन प्रिय द्वारपालों को मोक्ष के और पास ले आए।

वैकुण्ठ का द्वार आज भी वहाँ है—शांत, स्थिर, प्रकाश से भरा—और वही दो दिव्य प्रहरी फिर खड़े हैं, वही तेज, वही शक्ति और वही मुस्कान लिए। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान से दूर जाने का कोई मार्ग नहीं, क्योंकि कभी न कभी, किसी रूप में, किसी लीला में, भगवान स्वयं हमें वापस अपने पास ले ही आते हैं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

पूरे देश और गुजरात के लिए गौरव का क्षण

अहमदाबाद करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी!

अहमदाबाद में शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत@2047' के संकल्प और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के अथक प्रयासों को और मजबूती देगा

▸▸ गुजरात बनेगा देश की खेल राजधानी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ हम दुनिया का स्वागत करने को तैयार हैं : श्री हर्ष संघवी, उप मुख्यमंत्री

ऐसे मिली अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी :

कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी का अधिकार हासिल करने की भारत की यात्रा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट (सीएस) के साथ सुव्यवस्थित और सहयोगी प्रक्रिया के जरिए पूरी हुई है। इस प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत 9 जनवरी, 2025 को हुई थी, जब भारत को सीएस की ओर से 'लेटर ऑफ इन्टेंट' (एलओएल) का आमंत्रण मिला। इसके बाद, 29 जनवरी, 2025 को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के प्रमुख और सीईओ ने गुजरात का दौरा किया और राज्य के नेतृत्व के साथ बातचीत की और खेलों के लिए प्राथमिक विजन और तैयारियों का अवलोकन किया। इसके बाद 13 मार्च, 2025 को भारत ने 'लेटर ऑफ इन्टेंट' सौंपकर खेलों का आयोजन करने की औपचारिक प्रतिबद्धता दिखाई। इस दिशा में तैयारियां तेज होने पर, 29 अप्रैल, 2025 को भारत और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के बीच पहली बार वर्चुअल किक-ऑफ मीटिंग हुई, जिसमें वर्कस्ट्रीम, दस्तावेजों की आवश्यकता और समयसीमा निर्धारित की गई। मई, 2025 को बोली के टेक्निकल विकास के लिए एक विशेषज्ञ कंसल्टेंसी एजेंसी नियुक्त की गई। जून, 2025 में भारत का उच्च स्तरीय प्रतिनिदिमंडल लंदन गया और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अधिकारियों से मिलकर प्रस्ताव के टेक्निकल और संचालनात्मक आधार को और मजबूत बनाया। इसके बाद, 3 अगस्त, 2025 को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की टीम ने अहमदाबाद का दौरा किया और स्थानों, बुनियादी सुविधाओं, शासन व्यवस्था और खेलों की तैयारी का मूल्यांकन किया। 23 सितंबर, 2025 को भारत ने अपनी औपचारिक बीड प्रेजेंटेशन दी, जिसमें शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के विजन, क्षमता और तैयारियों को दर्शाया गया । विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 14 अक्टूबर, 2025 को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भारत की बीड को मजबूती, स्पष्टता और पेशेवर बताते हुए अहमदाबाद की मेजबान शहर के रूप में सिफारिश की। 26 नवंबर, 2025 को इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली ने वर्ष 2030 में शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स के मेजबान शहर के रूप में अहमदाबाद शहर की पुष्टि की। यह क्षण भारत, गुजरात और समग्र कॉमनवेल्थ खेल आंदोलन के लिए ऐतिहासिक क्षण है।

(जीएनएस)। गांधीनगर, 26 नवंबर : अंततः जिस क्षण का लोग आतुरतापूर्वक इंतजार कर रहे थे, उस घड़ी पर आधिकारिक मुहर लग गई है। जी हां, अहमदाबाद अब वर्ष 2030 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित 'कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली' की आज यानी बुधवार को हुई बैठक के अंत में इसकी घोषणा की गई। यह क्षण पूरे देश और गुजरात के लिए गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खेल की संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहन देने और उनकी दूरदर्शिता, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के अथक प्रयासों के चलते भारत खेलकूद के क्षेत्र में लगातार कदम बढ़ा रहा है। नतीजतन, आज कॉमनवेल्थ खेलों के शताब्दी संस्करण के अंतर्गत अहमदाबाद को 24वें कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है। इस समय जब 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का शताब्दी समारोह मनाने की तैयारी चल रही है, यह निर्णय भारत और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स मूवमेंट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगा। यह निर्णय कॉमनवेल्थ राष्ट्रों की खेल के प्रति श्रेष्ठता, एकता और संयुक्त प्रगति के 100 वर्षों के जश्न का एक शानदार प्रतीक बनेगा।

उल्लेखनीय है कि भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 'खेलो इंडिया' जैसे कार्यक्रम के जरिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज करने और उन प्रतिभाओं को निखारने में जुटे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निरंतर मार्गदर्शन के कारण देश को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है। इस क्षण का स्वागत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश के सभी नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि इसका श्रेय मोदी जी के सतत प्रयासों को जाता है। खेलों से जुड़ी मजबूत बुनियादी सुविधाओं और खिलाड़ियों को तैयार कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के समकक्ष खड़ा करने के कारण ही भारत और विशेषकर अहमदाबाद को यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा "अहमदाबाद, गुजरात और भारत के लिए यह अप्रतिम गौरव का क्षण है।" उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निरंतर प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि गुजरात अब देश देश की खेल राजधानी के रूप में उभरेगा। इतना ही नहीं, विकसित गुजरात से विकसित भारत की संकल्पना को और भी मजबूत करेगा।

इस अवसर पर केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा "अहमदाबाद में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 भारत की विकास यात्रा तथा खेल को राष्ट्रीय विकास के एक उपकरण के रूप में अपनाने की प्रतिबद्धता का उत्सव बनेगा।" यह मील का पत्थर 'विकसित भारत@2047' के हमारे विजन को मजबूती देगा, साथ ही यह प्रभावशाली, समावेशी और टिकाऊ खेल कार्यक्रमों का आयोजन करने में भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने उत्साहपूर्वक कहा "यह पल गुजरात और भारत के लिए अत्यंत गौरवशाली पल है। कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी संस्करण का आयोजन करना हमारे लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है। हम अहमदाबाद और भारत की प्रगति, समावेशी विचारधारा और आतिथ्य की झलक दर्शाने वाले इस जश्न के साथ दुनिया का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये खेल हमारी ढांचागत सुविधाओं और प्रतिभाओं को ही प्रदर्शित नहीं करेंगे, बल्कि एकता, टिकाऊ विकास और श्रेष्ठता जैसे हमारे मूल्यों का भी प्रतिबिंब होंगे।"

इस अवसर पर कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष डॉ. पी.टी. उषा ने कहा "कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने हम पर जो विश्वासा दिखाया है, उससे हम काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वर्ष-2030 के खेल केवल कॉमनवेल्थ आंदोलन के सौ वर्षों का जश्न ही नहीं, बल्कि आने वाली शताब्दी की नींव भी रखेंगे। ये खेल कॉमनवेल्थ देशों के सभी खिलाड़ियों, समुदायों और संस्कृतियों को मित्रता और प्रगति की भावना के साथ एकसूत्र में बांधेंगे।"

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अंतरिम अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे ने कहा "वर्ष-2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के मेजबान के रूप में अहमदाबाद शहर का आधिकारिक रूप से चयन भारत के कॉमनवेल्थ आंदोलन के लिए एक निर्णायक क्षण है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत इस सौ वर्ष पुराने खेल आयोजन में विशालता-भव्यता, युवापन, महत्वाकांक्षा, समृद्ध संस्कृति और अच्छी खेल भावना एवं खेल प्रेम लेकर आएगा। इस खेल आयोजन के लिए भारत का प्रस्ताव समावेशी और भविष्योन्मुखी कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के हमारे विजन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।"

आज की यह घोषणा पूरे भारत के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है, जो देश में बढ़ते विश्व स्तरीय खेल ढांचे और इस प्रकार के स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन करने की राष्ट्र की क्षमता को दिखाती है। 'न्यू एज गेम्स फॉर ए न्यू सेंचुरी' की थीम पर आधारित भारत की बोली (बीड) में सर्वसमावेशिता और मजबूती की अवधारणा निहित थी, जिसने कॉमनवेल्थ जनरल असेंबली को प्रभावित किया। यह थीम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट गेम्स के निर्धारित सिद्धांतों- किफायती, सुगम, सर्वसमावेशिता और दीर्घकालीन विरासत के बिल्कुल अनुरूप थी। अहमदाबाद का गेम्स प्लान संक्षिप्त, आधुनिक और खिलाड़ी-केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एशिया के सबसे बड़े मल्टी-स्पोर्ट विकास परियोजनाओं में से एक – सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव – गेम्स के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करेगा। कराई स्थित गुजरात पुलिस एकेडमी और नारणपुरा स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे अत्याधुनिक स्पोर्ट्स परिसर इस व्यवस्था में सहायक की भूमिका निभाकर आयोजन को मजबूती प्रदान करेंगे। इन स्पोर्ट्स परिसरों के आसपास एकीकृत परिवहन नेटवर्क, आवास की अत्याधुनिक सुविधाएं और डिजिटल बुनियादी ढांचा वर्ष 2023 से पहले अहमदाबाद की तैयारियों को सिद्ध करते हैं। इस खेल आयोजन के साथ पैरा-स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा और सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित स्थानों, कम उत्सर्जन वाले परिवहन संसाधनों और जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी में नए मानक स्थापित किए जाएंगे।

वर्ष-2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी 'विकसित भारत-2047' और 'विकसित गुजरात' की संकल्पनाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। इस गेम्स के आयोजन से गुजरात तेजी से देश की 'खेल राजधानी' के रूप में रूपांतरित होगा, इससे शहरी विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलने के साथ ही राज्य में रोजगार सृजन भी होगा और पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि होने से नागरिकों की जीवन शैली में भी आमूल बदलाव आएगा।

इस विजन को मुख्य राष्ट्रीय सुधारों – राष्ट्रीय खेल नीति 2025, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी (संशोधन) बिल 2025 – से मजबूत आधार मिलता है, जो भारतीय खेल इकोसिस्टम में पारदर्शिता, शासन और खिलाड़ी कल्याण को सामूहिक रूप से मजबूत बनाता है। राष्ट्रीय खेल नीति-2025 तथा राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी (संशोधन) बिल-2025 के अंतर्गत हुए बदलावों ने सामूहिक रूप से इस बोली को मजबूत सहयोग दिया। इस वजह से भारतीय स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में पारदर्शिता, प्रशासन और खिलाड़ियों के कल्याण को मजबूती मिली है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स भारत सरकार, गुजरात सरकार और कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीजीए इंडिया) की ओर से पारस्परिक सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की जनरल असेंबली के समक्ष इस प्रस्ताव को श्री अश्विनी कुमार, प्रधान सचिव, खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग, गुजरात सरकार, श्री कुणाल खरेचा, संयुक्त सचिव (खेल), भारत सरकार, श्री बंछानिधि पाणि, मनपा आयुक्त, अहमदाबाद महानगर पालिका, श्री रघु अय्यर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत किया था। इन अधिकारियों के समन्वित प्रयासों एवं सभी हितधारकों के साथ मिलकर जनरल असेंबली के समक्ष दी गई आकर्षक प्रस्तुति ने अहमदाबाद को इन खेलों की मेजबानी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पारंपरिक विरासत, समावेशिता की भावना और पारस्परिक सहयोग को केंद्र में रखकर अहमदाबाद में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का शताब्दी संस्करण अतीत का सम्मान करेगा, वर्तमान का जश्न मनाएगा और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट आंदोलन के भविष्य को एक नया आकार देगा।

पंचमहल सांसद श्री जादव ने किया गोधरा स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन विकास कार्यों का अवलोकन

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने आज गोधरा स्टेशन पधारे माननीय सांसद श्री राजपालसिंह जादव के साथ गोधरा स्टेशन का निरीक्षण किया और उन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने के लिए स्टेशन पर चल रहे कार्यों की जानकारी दी। माननीय सांसद श्री जादव ने मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके एवं वरिष्ठ अधिकारियों को यह कार्य गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पूरा करने के निर्देश दिये। श्री भडके ने माननीय सांसद को अवगत कराया कि अमृत भारत स्टेशन के तहत विकास का यह कार्य प्रगति पर है,संतोषजनक है और दिसंबर तक इसे पूरे करने का प्रयास है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने वडोदरा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों सहित गोधरा के जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में माननीय सांसद श्री राजपालसिंह जादव, मोरवा हडफ़ से माननीया विधायक श्रीमती निमिषाबेन सुथार, गोधरा एपीएमसी निदेशक श्री मालवदीप सिंह राउलजी ने रेल संबंधी सुझावों को मंडल रेल प्रबंधक एवं मंडल के वरिष्ठ रेल अधिकारियों से साझा किया।

माननीय सांसद श्री राजपालसिंह जादव ने गोधरा के पास रेल समपार फाटकों पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण में राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय से काम में तेजी लाने, गोधरा एवं डेरोल स्टेशन पर कोरोना काल से बंद स्टापेज़ को दुबारा शुरु करने, दिल्ली जाने के लिए गोधरा पर ट्रेन का स्टापेज़ देने तथा आनंद - गोधरा खंड का उपयोग करते हुए अहमदाबाद के लिए एक नई रेल सेवा शुरू करने का सुझाव दिया। माननीया विधायक श्रीमती निमिषाबेन ने रतलाम मंडल के संत रोड स्टेशन पर वलसाड इंटरसिटी के स्टापेज़ की मांग की।

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने माननीय सांसद के निर्देशन के अनुसार गोधरा स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन के कार्य गुणवत्ता को ध्यान में रख जल्द पूरा करने की बात कही।

श्री भडके ने कहा गोधरा के आसपास प्रलंबित रोड ओबर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज को राज्य सरकार के आर एंड बी विभाग तथा इरकॉन से बात कर इसे गति दी जायेगी। कोरोना काल से गोधरा एवं डेरोल पर निलंबित ट्रेन स्टापेज़ को फिर से शुरू करने के लिए प्रयत्न किया जायेगा।

वडोदरा मंडल जनप्रतिनिधियों के सुझावों को अमल कर यात्री सेवा को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत है।

76वें संविधान दिवस पर वडोदरा मंडल में उद्देशिका का सामूहिक पठन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वडोदरा मंडल के डीआरएम कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका (Preamble) का सामूहिक पठन कराया गया। इस अवसर पर सभी रेल कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं समृद्धि को सुदृढ़ करने का संकल्प दिलाया गया।

उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा ली कि वे भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के प्रति समर्पित रहेंगे तथा संविधान द्वारा प्रदत्त मूल्यों के पालन के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

इस वर्ष संविधान दिवस की थीम "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" रखी गई है। संविधान दिवस के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम न केवल डीआरएम कार्यालय के सभी विभागों में आयोजित किए गए, बल्कि वडोदरा, भरूच,अंकलेश्वर ,आनंद ,नडियाद ,गोधरा एवं एकतानगर सहित मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर भी प्रभावी रूप से संपन्न हुए।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के 4 जिलों को कवर करने वाली दो मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 224 किलोमीटर बढ़ जाएगा

परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2,781 करोड़ रुपये है

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज रेल मंत्रालय की दो परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 2,781 करोड़ है। ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के नेटवर्क का विस्तार करने और क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

देवभूमि द्वारका (ओखा) – कानालूस दोहरीकरण – 141 किलोमीटर

बदलापुर – कर्जत तीसरी और चौथी लाइन – 32 किलोमीटर

बढ़ी हुई लाइन क्षमता भारतीय रेलवे के लिए मोबिलिटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव रेल संचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'नए भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में व्यापक विकास करना है। इस विकास के माध्यम से, ये परियोजनाएं स्थानीय लोगों को "आत्मनिर्भर" बनाएंगी, जिससे उनके लिए रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत नियोजित की गई हैं, जिसका मुख्य ध्यान इंटीग्रेटेड प्लानिंग और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के 4 जिलों को कवर करने वाली ये दो परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 224 किलोमीटर का विस्तार करेंगी।

अनुमोदित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 585 गाँवों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिनकी आबादी लगभग 32 लाख है।

कानालूस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक अनुमोदित दोहरीकरण परियोजना, प्रमुख तीर्थ स्थल द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और इससे पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी।

बदलापुर – कर्जत खंड मुंबई उपनगरीय गलियारे का एक अभिन्न अंग है। तीसरी और चौथी लाइन की यह परियोजना मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी और यात्रियों की भविष्य की माँगों को पूरा करेगी, साथ ही दक्षिण भारत के लिए भी संपर्क सुविधा प्रदान करेगी।

यह मार्ग कोयला, नमक, कंटेनर, सीमेंट, पीओएल जैसी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण रूट है। क्षमता बढ़ाने के इन कार्यों से रेलवे पर अतिरिक्त 18 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की माल ढुलाई होगी। रेलवे परिवहन का एक पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल साधन होने के कारण, देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, दोनों में मदद करेगा। इन परियोजनाओं से प्रति वर्ष तेल आयात (3 करोड़ लीटर) में कमी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड (16 करोड़ किलोग्राम) उत्सर्जन कम होगा। उत्सर्जन में यह कमी 64 लाख (चौसठ लाख) पेड़ों के रोपण के बराबर है।

स्वदेशी से स्वाभिमान तक : गरवी गुर्जरी के माध्यम से गुजरात के हस्त कलाकार 'हर घर स्वदेशी' अभियान को दे रहे हैं वेग

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'हर घर स्वदेशी' अभियान को वेग देने में गुजरात सरकार की गरवी गुर्जरी का महत्वपूर्ण योगदान

'गरवी गुर्जरी' के सहयोग से गांधीनगर की रिद्धिबेन चावडा ने कलमकारी को आधुनिक जीवनशैली के साथ जोड़कर स्वदेशी वस्तुओं को दिया प्रोत्साहन, कपड़ों के अलावा होम डेकोर तथा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर भी रंग उतारे

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'हर घर स्वदेशी' तथा 'वोकल फॉर लोकल' के आह्वान को गुजरात राज्य सुदृढ़ समर्थन प्रदान कर रहा है। विशेषकर हस्तकला क्षेत्र में कारीगरों को प्रोत्साहन देकर राज्य ने स्वदेशी अभियान को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार 'आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के साथ स्वदेशी कारीगरी तथा परंपरागत हस्तकला को आधुनिक बाजार में नई पहचान दे रही है। इस प्रयास में गुजरात सरकार की संस्था 'गरवी गुर्जरी' महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गरवी गुर्जरी के मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन से गुजरात के कारीगरों के लिए नए आयाम खुले हैं, जिसमें गांधीनगर की कलमकारी कलाकार रिद्धिबेन चावडा की यात्रा उल्लेखनीय है।

कलमकारी को नई पहचान दिलाने के रिद्धि चावडा के प्रयास में गरवी गुर्जरी का साथ

वर्ष 2019 में जब रिद्धिबेन ने पहली बार हाथ में पेंटिंग ब्रश उठाया, तब उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि उनकी परंपरागत कला को नई पहचान मिलेगी और वह कला अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लेकर आएगी। रिद्धिबेन सुंदर कलमकारी (कपड़ों पर विभिन्न चित्रकारी करने की कला) करके भारतीय लोक परंपरा से प्रेरित सुंदर चित्र बनाती हैं। शुरुआती वर्षों में उन्होंने उत्कृष्ट कारीगरी कर हैंड-पेंटेड कलमकारी साड़ी, दुपट्टे तथा कुशन बनाए थे, जो पौराणिक कथाओं, प्रकृति एवं विभिन्न भावों को प्रतिबिंबित करते थे। रिद्धिबेन ने कहा, "कलमकारी सुंदर कार्य है, परंतु यह समय लेने वाली कला है और खर्चीली भी है। मैं कलमकारी को लोगों के लिए सुलभ बनाना चाहती थी और इस दौरान मेरा परिचय गरवी गुर्जरी से हुआ तथा वहाँ से मेरी कला की यात्रा प्रारंभ हुई।"

गरवी गुर्जरी ने मेरी कलमकारी को नई दिशा दी : रिद्धि चावडा

रिद्धिबेन ने जब कस्टमाइज्ड ऑर्डर लेने शुरू किए, उस दौरान उनका परिचय गरवी गुर्जरी से हुआ, जो परंपरागत कारीगरों को प्रोत्साहन देने वाला प्रसिद्ध मंच है। रिद्धिबेन ने गरवी गुर्जरी के सहयोग एवं मार्गदर्शन के माध्यम से परंपरागत कलमकारी कला को रोजमर्रा के उपयोगी उत्पादों में रूपांतरित कर स्वदेशी कला को घर-घर पहुँचाने का प्रयास किया। उन्होंने परंपरागत कपड़ों तक सीमित न रहते हुए आधुनिक होम डेकोर तथा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर भी रंग उतारे। उनके द्वारा गरवी गुर्जरी के सहयोग से तैयार की गई कैंडल, ट्रे, कोस्टर जैसी होम एक्सेसरीज व अन्य सुशोभन की वस्तुएँ लोकप्रिय बनी हैं। रिद्धिबेन का यह प्रयास प्रधानमंत्री के 'हर घर स्वदेशी' अभियान के उद्देश्य से सुसंगत है, जो घर-घर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर बल देता है।

20 से अधिक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर महिला सशक्तिकरण का उदारण प्रस्तुत किया

गरवी गुर्जरी के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के लिए दिवाली गिफ्ट ऑर्डर मिलने के बाद रिद्धि चावडा ने अपने वर्कशॉप में 20 से अधिक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर महिला सशक्तिकरण का उत्तर उदाहरण प्रस्तुत किया है। रिद्धिबेन ने कहा, "गुजरात सरकार की गरवी गुर्जरी संस्था के सहयोग से हमें अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुँचने का अवसर मिला है। हमारा ध्येय इस हस्तकला के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना तथा सृजनात्मकता को विस्तृत करना है।"

स्वदेशी अभियान से आत्मनिर्भरता की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ता गुजरात

राज्य के हस्तकला एवं हथकरघा कारीगरी की समग्र देश व विश्व में विशिष्ट पहचान स्थापित करने, उसे बनाए रखने तथा उसके विकास के मुख्य उद्देश्य के साथ कार्यरत गुजरात राज्य हथकरघा एवं हस्तकला विकास निगम (जीएसएचएचडीसी) गुजरात की इस परंपरागत वेल को निरंतर सींच रहा है। जीएसएचएचडीसी के गरवी-गुर्जरी एम्पोरियम के माध्यम से राज्य में ग्रामीण स्तरीय परंपरागत कला-कारीगरी के व्यवसाय से तेजी से प्रगति कर रहे हैं। गरवी-गुर्जरी हथकरघा-हस्तकला की श्रेष्ठ कृतियों का सृजन करने वाले सुदूरवर्ती-दूरदराजी गाँवों के हजारों कारीगरों के कला-कौशल तथा परिश्रम को लोगों तक पहुँचाता है और उनके उत्पादों के विक्रय में वृद्धि करने के निरंतर प्रयास करता है। गरवी गुर्जरी वह मंच है, जो कारीगरों को वित्तीय सहायता, डिजाइन मार्गदर्शन तथा मार्केट लिंकेज प्रदान करके 'स्वदेशी से स्वाभिमान' तक की यात्रा सुनिश्चित करता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रचंड जनसैलाब के अदम्य उत्साह के बीच 'सरदार@150 : राष्ट्रीय यूनिटी मार्च' का शुभारंभ कराया

करमसद से केवडिया तक 152 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के शुभारंभ अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, केन्द्रीय राज्य मंत्रियों श्रीमती अनुप्रिया पटेल एवं श्रीमती निमुबेन बांभणिया की विशेष उपस्थिति

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- 'सरदार पटेल@150 : यूनिटी मार्च' पदयात्रा राष्ट्रभक्ति का राजमार्ग प्रशस्त करेगी
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रेरित यह पदयात्रा सरदार पटेल को श्रेष्ठ श्रद्धांजलि है
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण का महाकार्य हो रहा है
- यह राष्ट्रीय पदयात्रा सरदार साहब के जीवन मूल्यों एवं आदर्शों को जानकर राष्ट्र निर्माण में सहभागी होने के लिए स्वर्णिम अवसर है
- देश में अनेक कल्याणकारी योजनाओं के सटीक क्रियान्वयन के कारण करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं

यह पदयात्रा कोई साधारण पदभ्रमण नहीं; बल्कि देश की एकता, अखडंता एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक समान लौह पुरुष सरदार पटेल को समर्पित विशेष आयोजन है : त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक

(जीएनएस)। गांधीनगर, 26 नवंबर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से सरदार साहब की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित करमसद से केवडिया तक की राष्ट्रीय पदयात्रा 'सरदार@150 : यूनिटी मार्च' को मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा ने फ्लैग ऑफ करके प्रस्थान कराया। आणंद जिले के करमसद में प्रचंड जनसैलाब के अदम्य उत्साह तथा 'जय सरदार' के गगनभेदी नारों की गूंज के साथ यह राष्ट्रीय पदयात्रा आगामी 6 दिसंबर को सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचेगी। 150 स्थायी पदयात्रियों के साथ आणंद के अलावा वडोदरा तथा नर्मदा जिलों से गुजरने वाली इस पदयात्रा का भव्य शुभारंभ कराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सरदार@150 : यूनिटी मार्च' पदयात्रा राष्ट्रभक्ति का राजमार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रेरित यह पदयात्रा सरदार पटेल को श्रेष्ठ श्रद्धांजलि है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने संविधान दिवस के अवसर पर डॉ. बाबासाहब आंबेडकर तथा संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करते हुए कहा कि विश्व नेता तथा 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के प्रेरणास्रोत श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में सरदार साहब की 150वीं जयंती भव्य रूप से मनाने का आयोजन हुआ है। इसी उपक्रम में जहाँ सरदार साहब का बचपन बीता था और जहाँ उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी, उस पवित्र भूमि करमसद से एकता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी-केवडिया तक यह यूनिटी मार्च आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लौह पुरुष सरदार पटेल को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए कहा कि सरदार साहब की यह अभूतपूर्व प्रतिमा विश्वभर में भारत के सामर्थ्य एवं गौरव के इतिहास का जीवंत प्रतीक बनी है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सरदार साहब ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में 562 देसी रजवाड़ों का विलय कर अखंड भारत का निर्माण किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरदार साहब के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार साहब द्वारा दिए गए राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य के साथ यह यूनिटी मार्च आयोजित हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पदयात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों से लोग सरदार साहब के जीवन मूल्यों को जानेंगे तथा राष्ट्रीय एकता का भाव अधिक सुदृढ़ होगा। उन्होंने सरदार साहब के मूल्यों के आधार पर नए भारत के निर्माण का महाकार्य हो रहा होने का उल्लेख करते हुए जोड़ा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम मंदिर में श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से ध्वजारोहण के साथ मंदिर निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। कुछ दिन पहले देश की श्रम शक्ति का सम्मान करने वालीं ऐतिहासिक चार श्रम संहिताएँ देश में लागू हुई हैं। सरदार साहब हमेशा श्रमिकों एवं किसानों के हित के लिए कार्यरत रहे, जिन्होंने अहमदाबाद के कामगारों के अधिकार तथा खेडा व बारडोली के किसानों को न्याय दिलाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर दिया था।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप कश्मीर से कन्याकुमार तक भारत एक एवं अखंड राष्ट्र बना है। श्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी कहा है कि राष्ट्र तथा समाज के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यंत ही आवश्यक है।

श्री पटेल ने कहा कि सरदार साहब का गरीबी दूर करने का सपना प्रधानमंत्री ने पूरा किया है। देश में अनेक कल्याणकारी योजनाओं के सटीक क्रियान्वयन के कारण करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। करोड़ों लोगों को उनके सपनों का घर मिला है तथा स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध हुआ है।

मुख्यमंत्री ने 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के माध्यम से विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने का अनुरोध करते हुए जोड़ा कि प्रधानमंत्री ने जब उनका संमग्र जीवन 'राष्ट्र प्रथम' के भाव के साथ देश को समर्पित किया है, तब हम सभी एकता के मूल मंत्र को आत्मसात कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। यही सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा ने कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रह कर अपने प्रेरक संबोधन में 'सरदार@150 : यूनिटी मार्च' अंतर्गत त्रिपुरा राज्य में मनाए गए उत्सव तथा आयोजन की रूपरेखा दी। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि यह पदयात्रा कोई सामान्य पदभ्रमण नहीं है; बल्कि देश की एकता, अखंडता तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक समान लौह पुरुष सरदार पटेल को समर्पित विशेष आयोजन है। उन्होंने राज्य की जनता तथा त्रिपुरा की ओर से उपस्थित सभी को अभिनंदन दिया।

श्री साहा ने इस वर्ष के राष्ट्रीय एकता दिवस उत्सव को विशेष बताया और 'सरदार@150 : यूनिटी मार्च' का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय पदयात्रा स्वतंत्र भारत के एकीकरण के शिल्पकार सरदार पटेल के योगदान का स्मरण कर देश के युवाओं में देशभक्ति, एकता तथा उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ बनाएगी। इस अभियान की मूल भावना 'एक भारत, आत्मनिर्भर भारत' से जुड़ी हुई है।

उन्होंने इस अवसर पर सरदार पटेल के ऐतिहासिक योगदान का स्मरण करते हुए आगे कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 562 देसी रजवाड़ों का विलय कर अखंड भारत का निर्माण सरदार साहब की असीमित दूरदर्शिता, दृढ़ नेतृत्व एवं राष्ट्र प्रेम को व्यक्त करता है। सरदार पटेल देश की एकता एवं संगठित राष्ट्रीयता के लिए जीवनभर समर्पित रहे।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014 से सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्णय की सराहना की। वर्ष 2015 में सरदार पटेल की 140वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' पहल की परंपरा शुरू की थी; जो देश की भाषा, संस्कृति एवं विरासत को जोड़ने का राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने गौरवपूर्वक कहा कि गुजरात में नर्मदा तट पर स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा है, देश की एकता तथा शक्ति की विशिष्ट प्रतीक है।

अंत में श्री साहा ने यूनिटी मार्च को देश को सुदृढ़, समृद्ध एवं एकताबद्ध बनाने का संकल्प व्यक्त करने वाली बताते हुए युवाओं से राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने, एकता को सर्वोच्च मूल्य के रूप में बनाए रखने और सरदार पटेल के संकल्पित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की।

आरंभ में राज्य के कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने स्वागत संबोधन में कहा कि सरदार साहब के जीवन तथा कार्यों को जानने के अलावा देश को एक करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को जन-जन तक पहुँचाने का यह अवसर है। गुजरात के दो सपूत सरदार पटेल तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विश्वनायक सिद्ध हुए हैं। श्री वाघाणी ने राष्ट्रीय पदयात्रा की रूपरेखा भी दी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा ने संविधान दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उत्सव को देश के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल, भगवान बिरसा मुंडा तथा वंदे मातरम् गीत के 150 वर्ष का उत्सव एक शुभ समन्वय है तथा यह देश के लिए गौरव का क्षण है।

राष्ट्रीय पदयात्रा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने जिस प्रकार देसी रजवाड़ों को एक कर अखंड भारत के निर्माण में महायोगदान दिया है, उसे सच्चे अर्थ में भावांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में 'सरदार@150 : यूनिटी मार्च' का आयोजन किया गया है।

श्री विश्वकर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरदार पटेल की 'एक भारत' की परिकल्पना साकार करने के लिए 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वदेशी वस्तुएँ अपनाने का अनुरोध करते हुए सभी को आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पबद्ध किया।

इस अवसर पर आणंद जिला कलेक्टर श्री प्रवीण चौधरी ने इस पदयात्रा को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रेषित शुभकामना संदेश का पठन किया।

महानुभावों ने कार्यक्रम से पूर्व सरदार पटेल के निवास स्थान पर जाकर वहाँ उन्हें स्मरणांजलि दी। इसके बाद शास्त्री मैदान में आयोजित कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार पटेल की जीवन यात्रा को दर्शाने वाला गीत रिमोट कंट्रोल से लॉन्च किया। इस अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकता पदयात्रा की 'माई भारत' द्वारा निर्मित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन बांभणिया, राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी, वित्त राज्य मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल, आणंद के सांसद श्री मीतेशभाई पटेल, खेडा के सांसद श्री देवूसिंह चौहाण, भाजपा महासचिव श्री सुनील बंसल, जिला अग्रणी श्री संजयभाई पटेल, आणंद जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हसमुखभाई पटेल, आणंद जिले के विधायक श्री योगेशभाई पटेल, श्री विपुलभाई पटेल, नडियाद के विधायक श्री पंकज देसाई, केन्द्रीय युवा एवं खेल सचिव श्री पल्लवी जैन, खेडा जिला कलेक्टर श्री अमित प्रकाश यादव, करमसद-आणंद महानगर पालिका आयुक्त श्री मिलिंद बापना, जिला विकास अधिकारी सुश्री देवहुति, जिला पुलिस अधीक्षक श्री गौरव जसाणी, गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री भाग्येश झा सहित देश एवं राज्य के अग्रणी पदाधिकारी, अधिकारी, युवा तथा विद्यार्थी भी राष्ट्रीय एकता पदयात्रा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित रहकर इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने।

राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन-जन के हृदय में पुनर्स्थापित करने के लिए सरदार@150 : यूनिटी मार्च देशवासियों में अनूठा प्राण फूँकेगी

▸▸ विश्व की सबसे ऊँची सरदार साहब की प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के प्रोजेक्ट की मुलाकात से सरदार वल्लभभाई पटेल के पौत्र श्री गौतमभाई पटेल प्रभावित

(जीएनएस)। गांधीनगर : भारत के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीय एकता, समरसता, सहयोग, स्वाभिमान एवं देशप्रेम की भावना अधिक प्रज्ज्वलित हो; इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अखंड भारत के शिल्पकार तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती समग्र देश में भव्यातिभव्य रूप से मनाने की प्रेरणा दी है। "हम सभी भारतीय हैं और भारत हमारा है। हम एक होकर रहेंगे, तो ही प्रगति कर सकेंगे।" सरदार साहब के राष्ट्रीय एकता के इस संदेश को जन-जन के हृदय में पुनर्स्थापित करने के लिए समग्र देश में 'सरदार@150 : यूनिटी मार्च' का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत गुजरात में करमसद से केवडिया तक आयोजित होने वाली इस पदयात्रा का शुभारंभ मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने करमसद से कराया है।

प्रधानमंत्री द्वारा सरदार साहब की विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का केवडिया में निर्माण कर वहाँ विभिन्न प्रोजेक्ट के जरिये केवडिया-एकता नगर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसकी सरदार वल्लभभाई पटेल के पौत्र श्री गौतमभाई पटेल ने मुलाकात ली और वे बहुत ही प्रभावित हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में श्री गौतमभाई पटेल ने प्रधानमंत्री के दिशादर्शन में हुए कामकाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि नर्मदा जिले के दुर्गम आदिवासी क्षेत्र में चल रहे महत्वाकांक्षी विकास प्रोजेक्ट की उनकी मुलाकात के दौरान स्थानीय नागरिकों ने प्रोजेक्ट को लेकर खुशी और संतोष व्यक्त किया है। इस प्रोजेक्ट द्वारा गाँवों में नर्मदा नदी का शुद्ध पानी घर-घर पहुँचाया जा रहा है। साथ ही बिजली की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसका सीधा प्रभाव स्थानीय लोगों के जीवन पर देखने को मिल रहा है। घर में टीवी, पंखे तथा अन्य विद्युत उपकरण चल रहे हैं, बच्चे स्कूल में नियमित रूप से जा रहे हैं और गाँव में ही गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय महिला गाइड ने बहुत ही बढ़िया ढंग से पूरे प्रोजेक्ट का विवरण समझाया। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि गाँव के युवाओं को अब शिक्षा तथा रोजगार के लिए गाँव छोड़कर शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा। इस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी स्तर का शैक्षणिक संस्थान भी शुरू होने वाला है, जिससे स्थानीय छात्रों को गाँव में रहकर ही उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसर मिलेंगे।

उन्होंने जोड़ा, "इतने बड़े पैमाने पर ऐसा विकास प्रोजेक्ट स्थापित करना और उसमें भी इतने सारे लोगों को जोड़ना वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है। गाँव के लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिलना सबसे बड़ी बात है। विशेषकर युवाओं को गाँव में ही शिक्षा तथा रोजगार मिलने की बात मुझे बहुत अच्छी लगी।"

उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस प्रोजेक्ट से आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोगों का जीवन धीरे-धीरे बदल रहा है और आने वाले समय में यह क्षेत्र का विकास का मॉडल बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. मानिक साहा ने करमसद स्थित सरदार पटेल के निवास स्थान पर सरदार साहब की प्रतिमा पर सूत की माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की

(जीएनएस)। गांधीनगर : सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उत्सव के अंतर्गत बुधवार को करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक एकता और अखंडता के मजबूत संदेश के साथ आयोजित हो रही राष्ट्रीय पदयात्रा के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने करमसद स्थित सरदार पटेल के निवास स्थान जाकर सरदार साहब की प्रतिमा पर सूत की माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. मानिक साहा सहित उपस्थित महानुभावों ने सरदार पटेल और विट्ठलभाई पटेल की प्रतिमाओं पर सूत की माला अर्पित की।

इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. मानिक साहा की विशेष उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने सरदार साहब की नई प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री सरदार पटेल के पैतृक निवास में सरदार साहेब की वंशावली (फैमिली ट्री) से भी अवगत हुए।

इस अवसर पर गुजरात के कृषि मंत्री श्री जीतू वाघाणी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी, वित्त, पुलिस और हाउसिंग राज्य मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल, आणंद के सांसद श्री मितेश पटेल, खेड़ा के सांसद श्री देवूसिंह चौहान, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, खंभात के विधायक श्री चिराग पटेल, अग्रणी श्री जगदीश पंचाल, आणंद कलेक्टर श्री प्रवीण चौधरी, खेड़ा कलेक्टर श्री अमित प्रकाश यादव, मनपा आयुक्त श्री मिलिंद बापना, रेंज आईजी सुश्री विधि चौधरी, जिला विकास अधिकारी सुश्री देवाहुति, पुलिस अधीक्षक श्री जी.जी. जसाणी, अग्रणी श्री संजय पटेल सहित कई गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी मौजूद रहे।

तीन ट्रेनों का विभिन्न स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए तीन ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैं:

1. 10 दिसंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19019 बांद्रा टर्मिनस–हरिद्वार एक्सप्रेस चांपानेर रोड और खरसालिया स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन का चांपानेर रोड स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 07:18 बजे/07:19 बजे तथा खरसालिया स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 07:48 बजे/07:49 बजे होगा। इसी तरह, 10 दिसंबर, 2025 को हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19020 हरिद्वार– बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस खरसालिया और चांपानेर रोड स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन खरसालिया स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 13:01 बजे/13:02 बजे तथा खरसालिया स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 13:20 बजे/13:21 बजे होगा।

2. 01 दिसंबर, 2025 को अहमदाबाद से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद–बोरीवली एक्सप्रेस बाजवा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 02:27 बजे बाजवा स्टेशन पहुंचेगी और 02:29 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर मंडल पर मंडल रेल प्रबंधक ने "संविधान दिवस" के अवसर पर राष्ट्रीय अखंडता की शपथ दिलाई

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर, 26 नवंबर, 2025 (बुधवार) को मंडल कार्यालय में पूरे उत्साह के साथ "संविधान दिवस"(Constitution Day) मनाया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भावनगर मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत के संविधान की उद्देशिका का पठन करवाया व संविधान के लिए संकल्पबद्ध और समर्पित रहने एवं राष्ट्रीय अखंडता की शपथ दिलवायी।

राष्ट्र में साम्प्रदायिक सदभाव बना रहे इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर सेवारत रहने की शपथ दिलवायी। संविधान दिवस के सन्दर्भ में मंडल रेल प्रबंधक ने भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की प्राप्ति के लिए, इन सभी के साथ व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करती भाईचारे की भावना की अभिवृद्धि के लिए संकल्पबद्ध होने की शपथ दिलवायी।

भावनगर मंडल के सभी स्टेशनों, डिपो, ऑफिस एवं वर्कशॉप पर सभी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा संविधान की उद्देशिका का पठन करके, पूरे उत्साह के साथ "संविधान दिवस" मनाया गया।

संविधान दिवस: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का भावपूर्ण स्मरण

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को संविधान दिवस के अवसर पर भारत के संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने गांधीनगर के सेंट्रल विस्टा गार्डन में स्थित बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा को भावांजलि देकर बाबासाहेब आंबेडकर की भाव-वंदना की।

इस अवसर पर गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, शहर भाजपा अध्यक्ष श्री आशिष दवे, गांधीनगर महानगरपालिका तथा जिला प्रशासन के अधिकारी और नगरजन उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से 2015 से हर वर्ष 26 नवंबर को देशभर में संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई है। इस दिन संविधान की प्रस्तावना का पठन भी किया जाता है।